तापमान
अधिकतम 38.0 डिग्री
न्यूनतम 28.0 डिग्री

हरिभूमि
रत्न भूमि
रायपुर, शुक्रवार 5 जून 2026

11 भीषण गर्मी में आई जनता को न दौड़ाएं, तीन दिन में करें...

12 तालाबों से हटेगा अतिक्रमण बस स्टैंड...

राजिम | फिंगेश्वर | छुरा | मुड़ागांव | रसेला | गरियाबंद | कोपरा | मैनपुर | देवभोग | पांडुका | छुईहा बेलर

आवश्यकता है
सपना ट्रेक्टर्स (Solis tractor) राजिम में
10 पद सेल्समैन एवं
4 मैकेनिक की तुरंत
आवश्यकता है।
न्यूनतम वेतन 8000 से
योग्यतानुसार अधिक दिया जायेगा।
पेट्रोलिंग + प्रति ट्रैक्टर्स नुसार
इंसेन्टिव अलग दिया जायेगा।
संपर्क : सपना ट्रेक्टर्स (Solis Tractor) फिंगेश्वर रोड राजिम
मो. 98271-12190, 9009371657,
7067000736

खबर संक्षेप

हैंडपंप सुधार से ग्रामीणों को मिली राहत

सुरसाबांधा। ग्राम पंचायत चौबेबांधा में पिछले कुछ दिनों से पेयजल समस्या के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। गांव के प्रमुख हैंडपंप में खराबी आने से लोगों को दूर-दराज के स्रोतों से पानी लाना पड़ रहा था। ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरपंच दुलीचंद आण्डे ने तत्काल पहल की और संबंधित विभाग से समन्वय कर हैंडपंप का सुधार कार्य करवाया। हैंडपंप की मरम्मत पूर्ण होने के बाद पुनः जल आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू हो गई है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। ग्रामीणों ने कहा कि समय पर समस्या का समाधान होने से पेयजल संकट से निजात मिली है। सरपंच दुलीचंद आण्डे ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है तथा भविष्य में ऐसी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गांव के नागरिकों ने उम्मीद जताई है कि पंचायत इसी प्रकार जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखेगी।

पॉलिटेक्निक कॉलेज में विभिन्न सीटों के लिए काउंसलिंग की तिथियां जारी

गरियाबंद। जिला मुख्यालय स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के लिए 30, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 15 और माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए 30 सीटें इस प्रकार कुल 75 सीटों में प्रवेश के लिए संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया का प्रथम चरण 11 जून से 15 जून 2026 और द्वितीय चरण 26 जून से 30 जून 2026 तक जारी रहेगी। इसी प्रकार संस्था स्तर पर काउंसलिंग 11 जुलाई से 16 जुलाई तक होगी। काउंसलिंग के संबंध में अधिक जानकारी के लिए सीजीडीटीई रायपुर डॉट सीजी स्टेट या सीजीडीटीई डॉट एडमिशन या पॉलिटेक्निक गरियाबंद के आधिकारिक वेबसाइट में जाकर अवलोकन कर सकते है।

पद्म पुरस्कार के लिए आवेदन10 जुलाई

गरियाबंद। भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार श्रृंखला के तहत पद्म विभूशण, पद्म भूशण तथा पद्म श्री पुरस्कारों के लिये वर्श 2027 के लिए प्रविश्टियां आमंत्रित की गई है। इन पुरस्कारों के नामांकन के लिए जिले के योग्य, पात्र व्यक्ति 10 जुलाई 2026 तक डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू अवार्ड जीओवी इन पर ऑनलाईन आवेदन भरते हुए नामांकन की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग गरियाबंद के कक्ष क्र. 80 में जमा कर सकते है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय से कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पष्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

विश्व पर्यावरण दिवस : उदंती सीतानदी बना संरक्षण, जलवायु और जनभागीदारी का राष्ट्रीय मॉडल

4 साल में 25 सौ एकड़ वनभूमि अतिक्रमण मुक्त दुर्लभ कछुआ और मालाबार हॉर्नबिल की वापसी

हरिभूमि न्यूज ⏭ मैनपुर

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व ने वन्यजीव संरक्षण, वन पुनजर्ऍवन और जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐसी प्रेरक कहानी प्रस्तुत की है, जो पूरे देश के लिए मिसाल बन रही है। पिछले चार वर्षों में यहां चलाए गए संरक्षण अभियानों के परिणाम अब जमीन पर स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। जहां एक ओर सैकड़ों हेक्टेयर वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, वहीं दूसरी ओर कई दुर्लभ और विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी प्रजातियों की वापसी ने इस जंगल की बदलती तस्वीर को और मजबूत किया है। उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में पिछले चार वर्षों के दौरान 956 हेक्टेयर अर्थात लगभग 2500 एकड़ वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस भूमि की अनुमानित नेट प्रेजेंट वैल्यू (एनपीवी) करीब 573 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह अभियान आसान नहीं था। अतिक्रमण हटाने और वन संरक्षण की कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम पर चार बार जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन इसके बावजूद अभियान लगातार जारी रहा और वनभूमि को पुनः प्रा—तिक स्वरूप में लौटाने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया।

जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में भी बड़ी भूमिका

अतिक्रमण हटाकर पुनजर्ऍवित किए गए वन क्षेत्र केवल वन्यजीवों के लिए ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पुनस्र्थापित वन बड़ी मात्र में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। इससे वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्र कम करने में मदद मिलती है।वन बहाली के कारण मिट्टी संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, स्थानीय तापमान नियंत्रण और वर्षा जल संरक्षण जैसे क्षेत्रें में भी सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। स्वस्थ वन परिदृश्य सूखा, अत्यधिक गर्मऍ और अन्य चरम मौसमी परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 956 हेक्टेयर (2500 एकड़) वनभूमि अतिक्रमण मुक्त, 550 से अधिक शिकारी, तस्कर और अतिक्रमणकारी गिरफ्तार, लगभग 573 करोड़ की वन संपदा संरक्षित, कई दुर्लभ प्रजातियों की वापसी से बढ़ा इको—टूरिज्म और रोजगार, वन विभाग की टीम पर 4 जानलेवा हमलों के बावजूद संरक्षण अभियान लगातार जारी रहा और आज इसके परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहे हैं।

शिकारियों और तस्करों पर बड़ी कार्रवाई- वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए चलाए गए विशेष अभियानों में पिछले चार वर्षों में 550 से अधिक शिकारी, वन्यजीव तस्कर और अतिक्रमणकारी गिरफ्तार अथवा निरुद्ध किए गए। कार्रवाई केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रही, बल्कि ओडिशा और महाराष्ट्र तक संयुक्त एंटी—पोचिंग ऑपरेशन चलाकर वन्यजीव अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया गया। इन सख्त कदमों का परिणाम यह हुआ कि वन्यजीवों को सुरक्षित वातावरण मिला और जंगलों में उनकी गतिविधियां बढ़ने लगीं।

दुर्लभ प्रजातियों की वापसी बनी सफलता की पहचान- संरक्षण प्रयासों का सबसे बड़ा प्रमाण रिजर्व में दुर्लभ वन्यजीवों की बढ़ती उपस्थिति है। हाल के वर्षों में मालाबार पाइड हॉर्नबिल, भारतीय विशाल गिलहरी, भारतीय उड़न गिलहरी, इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर, इंडियन पिट्टा, मूषक हिरण (माउस डियर), पैंगोलिन, चौसिंगा, ऊदबिलाव तथा ट्राइकारिनेट हिल टर्टल जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियों की मौजूदगी लगातार दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार मालाबार पाइड हॉर्नबिल सामान्यतः पश्चिमी घाट क्षेत्रें से जुड़ा माना जाता है, जबकि ट्राइकारिनेट हिल टर्टल का निवास हिमालयी और पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रें में माना जाता है। ऐसी प्रजातियों का उदंती सीतानदी में दिखाई देना यहां के वन पारिस्थितिकी तंत्र के बेहतर होने का संकेत माना जा रहा है।

बाघ गणना में भी मिले सकारात्मक संकेत- अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 के दौरान लगाए गए कैमरा ट्रैप में भी कई दुर्लभ वन्यजीव दर्ज हुए। इनमें माउस डियर, स्मॉल—क्लॉड ऑटर, यूरेशियन ऑटर और पैंगोलिन प्रमुख हैं। पैंगोलिन का पहली बार कैमरा ट्रैप में दर्ज होना वन विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि जंगलों में जैव विविधता लगातार मजबूत हो रही है।

नवाचारों से घटा मानव- वन्यप्राणी संघर्ष- उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व ने संरक्षण के क्षेत्र में कई आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी किया है। हाथियों की निगरानी के लिए ट्रैकिंग और अलर्ट ऐप विकसित किया गया है, जबकि थर्मल ड्रोन और एआई आधारित कैमरा निगरानी प्रणाली के माध्यम से वन्यजीवों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इन तकनीकी उपायों के कारण मानव—वन्यप्राणी संघर्ष की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। ग्रामीणों को समय रहते चेतावनी मिलने से जान—माल के नुकसान को कम करने में सफलता मिली है।हॉर्नबिल रेस्टोरेंट और कैनोपी कनेक्टिविटी जैसी अनूठी पहल।

नायब तहसीलदारों की हड़ताल खत्म तहसील कार्यालय में लौटी रौनक

हरिभूमि न्यूज ⏭ राजिम

नायब तहसीलदारों की हड़ताल समाप्त होने के बाद तहसील कार्यालयों में एक बार फिर रौनक लौट आई है। पिछले कई दिनों से चल रही हड़ताल के कारण राजस्व विभाग के अनेक कार्य प्रभावित हो रहे थे, जिससे आम नागरिकों, किसानों एवं ग्रामीणों को विभिन्न प्रमाण पत्रों और राजस्व संबंधी कार्यों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हड़ताल समाप्त होने की सूचना मिलते ही तहसील कार्यालय में लोगों की आवाजाही बढ़ गई। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा-खसरा एवं अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए बड़ी संख्या में लोग कार्यालय पहुंचने लगे हैं। लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया भी पुनः शुरू हो गई है। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि कृषि कार्यों एवं बैंकिंग प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज समय पर नहीं मिलने से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। हड़ताल समाप्त होने ⏭शेष पेज 10 पर

लंबित राजस्व कार्यों में आई तेजी

थनौद की 200 एकड़ जमीन की फर्जी रजिस्ट्री मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ⏭ अभनपुर

थाना अभनपुर पुलिस ने ग्राम थनौद की बहुमूल्य करोड़ों रुपये की भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कराने और सुनियोजित धोखाधड़ी करने के मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने मामले के चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

- फर्जी मुख्तियारनामा और हस्ताक्षर कर करोड़ों की जमीन पर कब्जे की कोशिश

आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 179/2026 के तहत भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 420, 467, 468, 470, 471 एवं 34 के अंतर्गत कड़ा मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ग्राम थनौद (तहसील गोबरा नवापारा, जिला रायपुर) स्थित विभिन्न खसरा नंबरों की जमीनों को हड़पने के लिए यह पूरा जाल बुना गया था। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम थनौद, तहसील गोबरा नवापारा, जिला रायपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1243/1, 1242/1, 1244/1, 1159/1, 1163/1, 1162/1 एवं 1162/2 का रकबा क्रमशः 0.1100, 0.0836, 0.0500, 0.1108, 0.1000, 0.2254 एवं 0.878 हेक्टेयर है, जो राजस्व अभिलेखों में केशव अवस्थी के नाम पर दर्ज है। आरोपियों ने कथित रूप से लगभग 200 एकड़ भूमि को हड़पने की नीयत से सुनियोजित षड्यंत्र रचकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। यह पूरी भूमि राजस्व अभिलेखों में मूल भू-स्वामी केशव अवस्थी के नाम पर दर्ज है। आरोपियों ने लगभग 200 एकड़ के इस विशाल भूभाग को हड़पने की नीयत से एक खतरनाक और ⏭शेष पेज 10 पर

74% से अधिक अभ्यर्थी रहे उपस्थित, नियमों का कड़ाई से हुआ पालन

17 केंद्रों में हुई शांतिपूर्वक प्री-डीएलएड परीक्षा

हरिभूमि न्यूज ⏭ गरियाबंद

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम), रायपुर द्वारा आयोजित प्री-डीएलएड प्रवेश परीक्षा गुरुवार को गरियाबंद जिले के 17 परीक्षा केंद्रों में पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा के सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस प्रवेश परीक्षा के लिए जिले में कुल 3,776 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था। इनमें से 2,811 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने पहुंचे, जबकि 965 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार परीक्षा में उपस्थिति का कुल प्रतिशत लगभग 74.44% दर्ज किया गया। परीक्षा निर्धारित समयानुसार सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की गई।

आधा घंटा पहले ही बंद कर दिए गए मुख्य द्वार- प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी गाइडलाइन का परीक्षा केंद्रों पर कड़ाई से पालन कराया गया। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए परीक्षा केंद्र का पूर्व अवलोकन करने और निर्धारित समय से दो घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। व्यापम के कड़े नियमों के तहत परीक्षा प्रारंभ होने के ठीक 30 मिनट पहले यानी सुबह 9:30 बजे परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार पूरी तरह बंद कर दिए गए, जिसके बाद किसी भी विलंब से पहुंचे परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र का कड़ाई से सत्यापन किया गया।

ड्रेस कोड और कड़े नियमों के बीच हुई जांच- नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापम ने इस बार भी सख्त दिशा-निर्देश लागू किए थे, जिसके तहत अभ्यर्थियों को केवल हल्के रंग के और आधी बांह वाले वस्त्र पहनकर आने की अनुमति दी गई थी। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, पर्स, बेल्ट, टोपी और आभूषण पहनकर अंदर जाने की मनाही थी। अभ्यर्थी अपने साथ केवल नीले या काले रंग का ⏭शेष पेज 10 पर

दो हाइवा में आमने-सामने भीषण भिड़ंत, केबिन में फंसे रहे चालक

हरिभूमि न्यूज ⏭ नवापारा-राजिम

नवागांव मुख्य मार्ग पर बुधवार देर रात दो हाइवा वाहनों में आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और दोनों गाड़ियो के चालक केबिन में ही फंस गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। ठीक उसी समय राजिम

विधायक रोहित साहू राजधानी रायपुर से वापस लौट रहे थे। जैसे ही उनकी नजर इस हादसे पर पड़ी, उन्होंने ⏭शेष पेज 10 पर

सीएम हेल्पलाइन 1076 : शिकायत, समाधान और जवाबदेही का नया सिस्टम

केंद्रीकृत तकनीकी सिस्टम, फोन, वॉट्सएप, वेबपोर्टल, मोबाइल एप और लिखित आवेदन, दर्ज होगी शिकायत

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

छत्तीसगढ़ में नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निराकरण के लिए राज्य सरकार 9 जून से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसका शुभारंभ करेंगे।

हरिभूमि फॉलोअप

यह केंद्रीकृत तकनीक आधारित व्यवस्था नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने, शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने तथा समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का मंच प्रदान करेगी, जिसकी निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय द्वारा की जाएगी। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के अंतर्गत संचालित इस सिस्टम का उद्देश्य नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने, शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने तथा समय पर समाधान तय करने विश्वसनीय मंच प्रदान करना है। नई व्यवस्था में शिकायतों का निराकरण 7 दिन में करने का प्रयास रहेगा। मुख्यमंत्री और उनका सचिवालय इसकी नियमित मॉनीटरिंग करेंगे, ताकि जनता को समय रहते राहत मिल सके। इस हेल्पलाइन का दूसरा पहलू यह भी है कि इसके जरिए कोई व्यक्ति सरकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी ले सकता है। पात्र हितग्राही को योजना का लाभ दिलाने के लिए मदद भी की जाएगी।

केंद्रीकृत और तकनीक आधारित प्रणाली

जानकारी के मुताबिक, सीएम हेल्पलाइन एक केंद्रीकृत और तकनीक आधारित शिकायत निवारण प्रणाली के तौर पर तैयार की गई है। इसके माध्यम से नागरिक फोन, वॉट्सऐप, वेबपोर्टल, मोबाइल ऐप और लिखित आवेदन के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक शिकायत को एक विशिष्ट नंबर प्रदान किया जाएगा, जिससे उसकी ट्रैकिंग संभव होगी।

चार स्तरीय सिस्टम से समाधान

शिकायतों के समाधान के लिए चार स्तरीय सिस्टम विकसित किया गया है। इसमें पहले ब्लॉक, जिला, संभागीय तथा अंत में सचिव या विभागाध्यक्ष स्तर पर शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा में समाधान नहीं होने की स्थिति में शिकायत स्वतः अगले स्तर पर प्रेषित हो जाएगी।

यूनिक नंबर से होगी ट्रैकिंग

सीएम हेल्पलाइन प्रणाली के पांच प्रमुख बिंदु हैं, इसमें यूनिक टोकन नंबर के माध्यम से शिकायत ट्रैकिंग, समय पर समाधान के लिए एसएलआर आधारित व्यवस्था, समाधान के बाद नागरिकों से संतुष्टि फीडबैक, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा एमआईएस डैशबोर्ड के माध्यम से सतत निगरानी शामिल हैं। सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे संचालित रहेगा। कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा तथा उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी

हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है। हेल्पलाइन पर दर्ज हर शिकायत के लिए एक तय समय सीमा निर्धारित की जाएगी, जिसके भीतर संबंधित विभाग को कार्रवाई करनी होगी। यदि किसी शिकायत का समाधान निर्धारित समय में नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस व्यवस्था से प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी और आम नागरिकों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

खबर संक्षेप

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन केवल राजनैतिक नौटंकी : कांग्रेस

रायपुर। कांग्रेस ने भाजपा सरकार द्वारा शुरू किये गए मुख्यमंत्री हेल्प लाइन को केवल राजनैतिक नौटंकी बताया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा, भाजपा सरकार जब से बनी है, उसे जनता

की समस्याओं के निराकरण से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री निवास में हर गुरुवार को जनता से मिलने का कार्यक्रम शुरू हुआ था, ढाई साल में आधा दर्जन गुरुवार को भी मुख्यमंत्री लोगों से नहीं मिले। भाजपा सरकार ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मंत्रियों के नियमित बैठने की घोषणा की, वह भी बंद हो गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी बहुत जल्दी उबाऊ कॉल सेंटर में तब्दील होगा फिर बंद हो जायेगा। उन्होंने कहा, राज्य में सभी विभागों के सरकारी काम कितने दिन में होगा, हर काम को करने के लिए समय अवधि निर्धारित कर सिटीजन चार्टर बनाया गया था और वह आज भी लागू है, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश के दफ्तरों में लगाया गया सिटीजन चार्टर का बोर्ड तक हटा दिया गया। किसी दफ्तर में कोई काम नहीं होता।

कोसरिया यादव समाज कार्यकारणी की बैठक 7 को

रायपुर। कोसरिया यादव समाज की रायपुर ग्रामीण परिक्षेत्र कार्यकारणी बैठक रविवार 7 जून को सुबह 11 बजे कुहेरा पाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुहेरा में आयोजित किया गया है। बैठक में कोसरिया यादव समाज रायपुर ग्रामीण परिक्षेत्र के समस्त पदाधिकारी, पाली अध्यक्ष व ग्राम गोटिया एवं समस्त यादव समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है। बैठक का उद्देश्य समाज को संगठित करने एवं युवाओं को आगे बढाने के विषय पर चर्चा की जाएगी।

लोकभवन में 3 दिवसीय मेडिटेशन शिविर

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका की पहल पर लोकभवन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए तीन दिवसीय मेडिटेशन (ध्यान) शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता, कार्यक्षमता तथा तनाव प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना है। हार्टफुलनेस संस्था, अमलेश्वर के सहयोग से आयोजित इस शिविर के प्रथम दिन ध्यान के महत्व और उसके व्यावहारिक लाभों पर विस्तार से जानकारी दी गई।

उर्वरक वितरण में बड़ा बदलाव हो रहा है लागू

केंद्र के ई-पोर्टल से मिलेगी खाद, छत्तीसगढ़ के बीजापुर और गरियाबंद बने पायलट जिले

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

केंद्र सरकार ने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के वितरण को अधिक पारदर्शी और जरूरत आधारित बनाने के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने की शुरुआत की है। इस नई प्रणाली के पायलट प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ के दो जिलों बीजापुर और गरियाबंद जिले का चयन किया गया है। खरीफ सीजन के दौरान इन जिलों में किसानों को उर्वरक वितरण ई-पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिससे खाद की उपलब्धता, वितरण और खपत की निगरानी रियल टाइम में की जा सकेगी। राज्य के कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था कारगर रही तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

खास खबर

नई व्यवस्था ऐसे समय लागू की जा रही है जब हर वर्ष खरीफ सीजन में खाद की कमी, लंबी कतारों, कालाबाजारी और जरूरत से अधिक खरीदारी की शिकायतें सामने आती रही हैं। सरकार का मानना है कि डिजिटल प्रणाली से इन समस्याओं पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। हालांकि जून के प्रथम सप्ताह में राज्य में खेती-किसानी की गतिविधियां शुरु हो गई है। राज्य के कई अलग-अलग जिलों से किसानों की ये परेशानी सामने आ रही है कि उन्हें सोसाइटी से खाद नहीं मिल पर रही है। दूसरी ओर कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सोसाइटियों में खाद भंडारण पिछले साल से अधिक मात्रा में किया गया है। कुछ सोसाइटियों में खाद की कमी इसलिए हो सकती है, क्योंकि खाद परिवहन को लेकर कई बार समस्याएं आती हैं।

अब ऑनलाइन पंजीयन और डिजिटल निगरानी पर जोर

क्या है नई व्यवस्था

नई प्रणाली के तहत किसानों को उर्वरक प्राप्त करने के लिए पहले पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। किसान अपनी फसल, भूमि और आवश्यक उर्वरक की जानकारी दर्ज करेंगे। इसके आधार पर उन्हें उर्वरक आवंटित किया जाएगा। कई राज्यों में परीक्षण के दौरान ई-टोकन, क्यूआर कोड और भूमि रिकॉर्ड आधारित सत्यापन जैसी व्यवस्थाएं भी अपनाई गई हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला उर्वरक वास्तविक किसानों तक पहुंचे और उसकी अनावश्यक जमाखोरी न हो।

किसानों की चिंता भी कम नहीं

हालांकि नई व्यवस्था को लेकर किसानों और सहकारी समितियों के बीच कुछ आशंकाएं भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता और समय पर पंजीयन जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। मध्य प्रदेश में लागू की गई इसी तरह की डिजिटल प्रणाली से कतारें कम होने और वितरण में पारदर्शिता बढ़ने के दावे किए गए हैं, लेकिन शुरुआती दौर में किसानों को नई प्रक्रिया समझने में समय लगा था।

बीजापुर और गरियाबंद क्यों महत्वपूर्ण

बीजापुर और गरियाबंद का चयन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दोनों जिलों की कृषि परिस्थितियां एक-दूसरे से काफी अलग हैं। बीजापुर नक्सल प्रभावित और आदिवासी बहुल जिला है, जबकि गरियाबंद में धान उत्पादन प्रमुख है। ऐसे में केंद्र सरकार को यह समझने का अवसर मिलेगा कि डिजिटल उर्वरक वितरण प्रणाली दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों और सामान्य कृषि क्षेत्रों में किस तरह काम करती है। जानकारों का मानना है कि यदि इन दोनों जिलों में प्रयोग सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में इसे पूरे छत्तीसगढ़ और देश के अन्य राज्यों में लागू किया जा सकता है।

खाद संकट और कालाबाजारी रोकने की कोशिश

केंद्र सरकार का दावा है कि नई प्रणाली से उर्वरक की उपलब्धता और स्टॉक की निगरानी आसान होगी। अधिकारी यह देख सकेंगे कि किस जिले, ब्लॉक या दुकान में कितना स्टॉक उपलब्ध है और किस किसान ने कितना उर्वरक खरीदा है। इससे कालाबाजारी, फर्जी बिक्री और औद्योगिक उपयोग के लिए उर्वरक की अवैध निकासी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

खरीफ सीजन में होगी असली परीक्षा

छत्तीसगढ़ में धान की बुआई का मौसम शुरू होने वाला है और इसी दौरान उर्वरकों की मांग सबसे अधिक रहती है। ऐसे में बीजापुर और गरियाबंद में शुरू की जा रही ई-पोर्टल आधारित व्यवस्था की सफलता या विफलता पर राज्य और केंद्र दोनों की नजर रहेगी। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो खाद वितरण की पारंपरिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर, केंद्र सरकार उर्वरक वितरण को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर जरूरत के अनुसार खाद, सही किसान तक खाद की व्यवस्था विकसित करना चाहती है।

विभागों और कार्यों का किया गया स्पष्ट आवंटन

सीएम सचिवालय में अफसरों को सौंपे नए कार्यभार

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यों में व्यापक फेरबदल करते हुए नवीन उत्तरदायित्व सौंपे हैं। इस प्रशासनिक व्यवस्था के तहत प्रमुख सचिव से लेकर संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को उनके विभागों और कार्यों का स्पष्ट आवंटन किया गया है।

सुबोध कुमार सिंह, प्रमुख सचिव

इन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय के समस्त प्रशासनिक और समन्वय कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। इनके पास राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, निर्वाचन आयोग, लोकपाल, केंद्रीय मंत्रालय, अन्य राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री कार्यालयों, नीति आयोग और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित विषय होंगे। इसके अलावा, ये विभिन्न आयोगों से संबंधित कार्य, मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रथम श्रेणी अधिकारियों का प्रबंधन, मुख्यमंत्री विशेष परियोजनाएं सीएम हेल्पलाइन, तथा कलेक्टर/एस.पी./ डीएफओ कांफ्रेंस। साथ ही, ये सामान्य प्रशासन, वित्त, विधि एवं विधायी कार्य, खनिज साधन, तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रभारी रहेंगे।

खास खबर

मुकेश कुमार बंसल, सचिव

इन्हें जनसंपर्क, ऊर्जा, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन, मछली पालन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, जल संसाधन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का कार्यभार सौंपा गया है।

पी. दयानंद, सचिव

ये मुख्यमंत्री सहायता कोष (विवेकाधीन निधि) एवं स्वास्थ्य सहायता योजना, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.), वाणिज्यिक कर (पंजीयन) तथा संसदीय कार्य विभाग के कार्यों का संचालन करेंगे।

राहुल भगत, सचिव

इन्हें गृह, जेल, परिवहन, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग का उत्तरदायित्व दिया गया है। साथ ही, मुख्यमंत्री निवास के समन्वय और बिल भुगतान संबंधी कार्य भी इनके अधीन होंगे।

रजत बंसल, विशेष सचिव

ये सुशासन तिहार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आवास एवं पर्यावरण, स्कूल शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग का कार्य देखेंगे।

प्रभात मलिक, संयुक्त सचिव

इन्हें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, श्रम, नगरीय प्रशासन एवं विकास, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, तथा जन शिकायत निवारण विभाग का कार्य आवंटित किया गया है।

संभाग एवं जिला स्तरीय निगरानी व्यवस्था

शासन ने संभागों के प्रभावी संचालन के लिए अधिकारियों को विशेष प्रभार दिए हैं, जिसके तहत वे संभाग/जिले की प्रमुख योजनाओं और महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा करेंगे।
रायपुर संभागः मुकेश कुमार बंसल
बिलासपुर संभागः पी. दयानंद,
बस्तर संभागः राहुल भगत
सरगुजाः संभाग रजत बंसल
दुर्ग संभागः प्रभात मलिक।
आदेशानुसार, मुख्यमंत्री सचिवालय के सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ अपने कर्तव्यों का संपादन करेंगे और मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।

प्रदेश के पर्यटन स्थलों, हस्तशिल्प एवं स्थानीय उत्पादों को मिलेगा राष्ट्रीय मंच

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक देश के सबसे बड़े ट्रेड फेयर भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय मंच मिलेगा। इसी संबंध में कैट के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल से मुलाकात कर महोत्सव की रूपरेखा, पर्यटन आधारित व्यापारिक संभावनाओं और प्रदेश की सहभागिता को लेकर विस्तृत चर्चा की। कैट के राष्ट्रीय वाईस चेयरमैन अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमैन विक्रम सिंहदेव, अध्यक्ष परमानंद जैन ने संयुक्त रूप से बताया कि भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के संबंध में गुरूवार को कैट अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल से मुलाकात कर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले भारतीय व्यापार महोत्सव के संबंध में विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन, वन एवं इको-टूरिज्म, होटल एवं ट्रैवल उद्योग, हस्तशिल्प, जनजातीय उत्पादों तथा स्थानीय उद्यमों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के विषय पर चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पर्यटन क्षमता को देशभर के व्यापारियों, निवेशकों एवं उपभोक्ताओं के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने महोत्सव में राज्य के पर्यटन विभाग, होटल उद्योग, ट्रैवल ऑपरेटर्स, हस्तशिल्प उत्पादकों, महिला स्व-सहायता समूहों एवं स्थानीय उद्यमियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के पर्यटन एवं व्यापार क्षेत्र को नई गति मिलेगी तथा रोजगार एवं निवेश के नए अवसर सृजित होंगे।

रेत खनन नियमों एवं वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप हो : राज्यपाल

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा है कि राज्य में रेत खनन निर्धारित नियमों एवं वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण और विकास दोनों उद्देश्यों को समान रूप से साधा जा सके। राज्यपाल ने राज्य में चल रही ड्रोन आधारित निगरानी और खनिज 2.0 पोर्टल के माध्यम से मॉनिटरिंग की जानकारी लेते हुए इसकी सराहना की। राज्यपाल ने खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद से लोकभवन में चर्चा के दौरान यह बात कही। राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ की नदियों और बड़े नालों में रेत खनन की गतिविधियों को वैज्ञानिक, संतुलित और व्यवस्थित ढंग से संचालित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि रेत राज्य के विकास और आधारभूत संरचना निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए इसके उपयोग और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि इनके अनियंत्रित दोहन से पर्यावरण और जल संसाधनों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहती है।

अवैध खनन पर हो प्रभावी नियंत्रण

राज्यपाल ने कहा कि नदियों और बड़े नालों की प्राकृतिक संरचना तथा जलधारण क्षमता को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अनियोजित खनन गतिविधियों से नदी तटों, भू-जल स्तर और स्थानीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए खनन कार्यों की नियमित निगरानी और अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि नदियों एवं जलस्रोतों की क्षमता बढ़ाने तथा भू-जल संरक्षण के लिए दीर्घकालिक और समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

रेत खनन क्षेत्र का हो वैज्ञानिक अध्ययन

राज्यपाल ने निर्देश दिए कि रेत खनन से संबंधित क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जैसे विशेषज्ञ संस्थानों से सर्वे और तकनीकी अध्ययन कराया जा सकता है, ताकि खनन गतिविधियों के प्रभावों का आकलन कर बेहतर प्रबंधन की दिशा में कदम उठाए जा सकें। राज्यपाल डेका ने कहा कि रेत जैसे खनिज संसाधनों का उपयोग राज्य के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पेज 9 के शेष...

नायब तहसीलदारों ...

से अब उनके कार्यों में गति आएगी और आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध हो सकेंगे। तहसील कार्यालय परिसर में फिर से चहल-पहल दिखाई दे रही है। कर्मचारी लंबित प्रकरणों के निराकरण में जुट गए हैं, वहीं आमजन भी अपने जरूरी कार्यों को लेकर कार्यालय पहुंच रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि हड़ताल के दौरान रुके हुए कार्यों का शीघ्र निपटारा कर प्रशासन आम नागरिकों को राहत प्रदान करेगा। हड़ताल समाप्त होने से क्षेत्र के नागरिकों ने राहत की सांस ली है और उम्मीद जताई है कि राजस्व सेवाएं अब पहले की तरह सुचारू रूप से संचालित होती रहेंगी।

थनौद की 200...

सुनियोजित षड्यंत्र रचा था। **फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और कूटरचित हस्ताक्षरों का खेल-** जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी मिर्जा परवेज ने अपने साथी अब्दुल नईम, आरिफ अली एवं रोमेश पाण्डेय के साथ मिलकर वर्ष 2023 में इस धोखाधड़ी की नींव रखी थी। आरोपियों ने असली भू-स्वामी केशव अवस्थी की जगह किसी अन्य डमी व्यक्ति को खड़ा कर दिया। इसके बाद उस अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से कूटरचित हस्ताक्षर, फर्जी फोटो और अंगूठे के निशान लगाकर अपने नाम पर एक फर्जी मुख्तियारनामा तैयार करवा लिया। इस जाली दस्तावेज के सहारे भूमि को पहले अब्दुल नईम और बाद में खुद मिर्जा परवेज के नाम पर फर्जी तरीके से पंजीकृत कराने के लिए उप पंजीयन कार्यालय रायपुर में पेश किया गया था।

शिकायत के बाद एक्शन में पुलिस; जब्त हुए दस्तावेज व पहचान पत्र- इस महाघोटाले की भनक लगते ही शिकायतकर्ता वाणी पवार ने मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्तियारनामा एवं विक्रय दस्तावेजों की बारीकी से जांच की और महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेख जब्त किए। आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस ने 2 जून 2026 को बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से फर्जीवाड़े और मुख्तियारनामा तैयार करने के दौरान इस्तेमाल किए गए पहचान दस्तावेज व दो आधार कार्ड भी साक्ष्य के रूप में बरामद किए हैं। पर्याप्त दस्तावेजी सबूत मिलने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर आरोपियों के नाम मिर्जा परवेज (मुख्य योजनाकार), अब्दुल नईम (उम्र 53 वर्ष), वसीम हुसैन (उम्र 33 वर्ष), मोहम्मद खलील (उम्र 28 वर्ष)।

जांच जारी- थाना प्रभारी ने बताया कि जमीन धोखाधड़ी के इस बड़े सिंडिकेट में कुछ अन्य आरोपियों और मददगारों के शामिल होने की पूरी आशंका है। पुलिस की विशेष टीमें फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं और मामले की विवेचना को आगे बढ़ाया जा रहा है। जल्द ही कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।

17 केंद्रों में हुई...

बॉल पेन ही ले जा सके। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों के लिए गरिमा का ध्यान रखते हुए अलग से अतिरिक्त सुरक्षा जांच की व्यवस्था की गई थी।

प्रशासनिक अधिकारियों ने किया केंद्रों का औचक निरीक्षण- परीक्षा के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की फ्लाइंग स्क्वाड (उड़नदस्ता) टीमों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का सघन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा केंद्रों के भीतर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था व पहचान सत्यापन की समुचित निगरानी की गई। जिला प्रशासन ने परीक्षा संपन्न होने के बाद राहत की सांस लेते हुए बताया कि संपूर्ण जिले में परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हुई। पूरे गरियाबंद जिले में कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना, नकल के मामले या व्यवस्था में व्यवधान की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

दो हाइवा में आमने...

तत्काल अपनी गाड़ी रुकवाया और बिना देर किए डायल-112 को सूचना दी तथा स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। हादसे में दोनों हाइवा वाहन के चालक केबिन में बुरी तरह फंस गए थे। विधायक रोहित साहू स्वयं मौके पर मौजूद रहे और ग्रामीणों के सहयोग से करीब एक से डेढ़ घंटे तक लगातार राहत कार्य में जुटे रहे। काफी मशक्कत के बाद दोनों घायल चालकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद तत्काल 112 वाहन के माध्यम से अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है।

विधायक की तत्परता की हो रही सराहना- खास बात यह है कि दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विधायक रोहित साहू की तत्परता और मानवीय पहल की जमकर सराहना की। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर मदद नहीं मिलती तो हादसा और भी गंभीर रूप ले सकता था। घटना की सूचना मिलते ही नवापारा पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था बहाल कराई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

कांग्रेस जिला अध्यक्षों का विशेष प्रशिक्षण शिविर 21 से 30 तक

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

छत्तीसगढ़ के चम्पारण में 21 से 30 जून के बीच कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण अभनपुर के एक रिसार्ट में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मार्गदर्शन देने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी आएंगे।

ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य जिला अध्यक्षों को वैचारिक रूप से मजबूत करना और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करना है। बताया जाता है कि दस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा के जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ पीसीसी द्वारा 41 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पांच माह पूर्व की गई थी। नियुक्ति के बाद से उनकी पूरी गतिविधियों की हर तीन माह में समीक्षा पीसीसी को करने कहा गया है। जिला अध्यक्षों को ज्यादा अधिकार देने की वकालत राहुल गांधी ने की थी। इसी आधार पर उन्हें प्रशिक्षण देकर संगठन के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में बताया जाएगा।

संगठन के वरिष्ठ नेता देंगे प्रशिक्षण

ट्रेनिंग कार्यक्रम में केंद्रीय संगठन के कई वरिष्ठ नेताओं के अलावा स्थानीय वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन देंगे। कार्यक्रम का शेड्यूल आने वाले दिनों में जारी किया जाएगा। बताया गया है कि कांग्रेस संगठन के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव केसी वेणुगोपाल इस दौरान आएंगे। वे संगठन में काम करने के बारे में बताएंगे। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिनों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी संबोधित करेंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिला अध्यक्षों को उनके अधिकार और संगठन के बारीकियों के बारे में बताएंगे।

खबर संक्षेप

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार केंद्र में रोजगार मेला 19 जून को

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ.ग. रागपुर के निर्देश पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, गरियाबंद द्वारा कार्यालय परिसर में निजी प्रतिष्ठान स्वाभिमान फाइनेंस प्रा० लि० राजिम रोड, गजरकट्टा गरियाबंद एवं ग्लोबल एच.आर. साल्यूशन एण्ड जॉब कंसल्टेन्ट लिमिटेड दुर्ग से प्राप्त रिक्त पद फील्ड स्टॉफ, सिक्यूरिटी गार्ड के कुल 120 रिक्त पदो पर भर्ती के लिए शुक्रवार, 19 जून 2026 को प्रातः 10:00 से शाम 3:00 बजे तक रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें निजी प्रतिष्ठान में रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। निजी प्रतिष्ठान में रोजगार के इच्छुक ऐसे आवेदक जो न्यूतग 10वीं, 12वीं, स्नातक की योग्यता रखते है, अपने दो पासपोर्ट साईज फोटो एवं समस्त शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता संबंधी अंकसूची, प्रगाण पत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति के साथ निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर रोजगार मेला का लाभ उठाएं। रोजगार मेला में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी को ई-रोजगार पोर्टल या छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है।

देवभोग और मैनपुर को मिलेंगे पानी टैंकर, 24 लाख स्वीकृत

गरियाबंद। बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव की अनुशंसा पर कलेक्टर बीएस उइके ने 05 कार्यों के लिए 15 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार विकासखण्ड देवभोग अंतर्गत ग्राम पंचायत सीनापाली, ग्राम पंचायत गिरसुल, ग्राम पंचायत रोहनागुड़ा, ग्राम पंचायत धौराकोट, ग्राम पंचायत मुड़ागॉव में 01-01 नग पानी टैंकर प्रदान करने के लिए 03-03 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त कार्यो के लिए क्रियान्वयन एजेंसी का दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत देवभोग को सौंपा गया है। इसी प्रकार विकासखण्ड मैनपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत भैंसमुड़ी, चिखली और खरीपथरा में 01-01 नग पानी टैंकर प्रदान करने के लिए 03-03 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त कार्यो के लिए क्रियान्वयन एजेंसी का दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपुर को सौंपा गया है।

रेलवे फाटक के पास एक्सीडेंट में कार क्षतिग्रस्त

महासमुंद। न्यायालयीन कार्य से महासमुंद आए अधिवक्ता की कार को एक वाहन चालक ने ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। कोतवाली थाने में प्रार्थी नितिन चतुर्वेदी निवासी रायपुर ने रिपोर्ट लिखाई है कि 3 जून को अपनी कार सीजी 04 पीबी 1508 से अपने साथी अधिवक्ता अमन जांगडे एवं एक परिचित श्याम सुंदर गुप्ता के साथ रायपुर से महासमुंद शहर की ओर न्यायालयीन कार्य से आ रहा था। शाम 05 बजे के आसपास महासमुंद रेलवे फाटक के पास कार सीजी 06 एचई 8881 के चालक ने उसकी गाड़ी को पीछे से ठोकर मार दिया, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। मामले की रिपोर्ट पर आरोपी वाहन चालक के विरूद्ध धारा 281, 351(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

न्यायालय तहसीलदार-छुरा, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./ /ब-121 / वर्ष 2022-23

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका यशपाल वल्द ललेश्वर, जाति-गोंड, ग्राम-गिधनी प.ह.नं. 11 रा.नि.मं. खड़मा, तहसील - छुरा, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) ने अपने स्वयं/माता/पिता/पुत्र/पुत्री/भाई/बहन/दादी मानकुंवर के जन्म प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र 01 वर्ष की अवधि के अंदर पंजीयन नही कराने के कारण विलंबित जन्म-मृत्यु का पंजीयन किये जाने हेतु उप-पंजीयक (जन्म-मृत्यु) को आदेशित करने बाबत (जन्म - मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) एवं छ.ग. जन्म - मृत्यु रजि. नियम 2001 के नियम 9 (3) के प्रयोजन हेतु) शपथ पत्र में अनुपलब्धता प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति / संस्था / शासकीय / अर्द्ध-शासकीय निकाय या अन्य संस्था को किसी भी प्रकार की दावा / आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 16/06/2026 तक इस न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दावा/ आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले दावा / आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 01/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद- मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
छुरा

मुहर

सुशासन तिहार : गौरघाट में सुशासन तिहार का आयोजन, 14 गांवों के सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे

सुशासन तिहार में मिले 400 आवेदन, मैनपुर को नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया शुरू

हरिभूमि न्यूज ⏭ मैनपुर

तहसील मुख्यालय मैनपुर से 03 किमी दूर ग्राम गौरघाट में गुरुवार को छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वपूर्ण सुशासन तिहार का आयोजन किया गया इसमें 14 ग्रामों के सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए और 400 आवेदन प्राप्त हुए। सुबह 10 बजे से शिविर स्थल मे क्षेत्र से ग्रामीणो की भीड़ आना प्रारंभ हो गया था। इस शिविर का शुभारंभ गरियाबंद जिले के कलेक्टर भगवान सिंह उइके, जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम, भाजपा जिला के पूर्व उपाध्यक्ष योगेश शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सरिता ठाकुर, भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोश यादव, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश मंत्री नंदनी नेताम, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश साहू, नरोत्तम साहू, दिलीप साहू, जनपद अध्यक्ष श्रीमति मोहना नेताम, जनपद उपाध्यक्ष नंदकुमारी राजपूत, जनपद सभापति तपे"वर ठाकुर, जनपद सदस्य मैनपुर कुमारी बाई पटेल, सुखचंद धुरव, जामून देवी, प्रताप सिंह मरकाम, एसडीएम मैनपुर हिते"वरी बाघे, वन विभाग के एसडीओ मनोज चंद्राकर, एसडीओपी पुलिस ओमप्रकाश खुजुर एवं क्षेत्र के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियो की उपस्थिति मे पूजा अर्चना कर किया गया। गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि शासन का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रे में शिविरों के माध्यम से आम जनता तक पहुंच सुनिश्चित कर उनके समस्याओं का समाधान किया जा रहा है इस क्षेत्र के लिए जो पुल-पुलिया स्वीकृत हो चुकी है इनमें से कुछ बन रही है और कुछ टेंडर प्रक्रिया पर है 12 नए उपस्वास्थ्य केंद्र के लिए करोड़ो रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है जिससे आमजनों को दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। कलेक्टर श्री उइके ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के नाम चस्पा करें साथ ही खाद की आपूर्ति रकबे के आधार पर सहकारी समितियों से किसान प्राप्त कर सकते है किसानों को रासायनिक खाद के अंधाधुंध उपयोग की जगह नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जैसे वैकल्पिक उत्पादों का उपयोग कर कृषि कार्यों को उपयोग करने का आग्रह किया किसानों को एग्रिस्टेक पंजीयन अनिवार्य है उन्होंने किसानों से जल्द से जल्द पंजीयन पूर्ण करने को कहा साथ ही बचे हुए राशन कार्ड एवं महतारी वंदन के हितग्राहियों से ई–केवाईसी करवाने की अपील की है। कलेक्टर ने कहा मैनपुर को नगर पंचायत बनाने का मांग किया गया है उन्होने इसके लिए मंच से ही अधिकारियो को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेश शर्मा ने कहा भाजपा सरकार गांव गरीब किसानो की सरकार है आज सरकार लोगो के बीच जाकर सुशासन तिहार के माध्यम से उनकी समस्याओ को सुन रही है और समस्याओ का मौके पर समाधान किया जा रहा है। उन्होने कहा मैनपुर को नगर पंचायत बनाने की मांग के साथ ही सलफ जलाशय, मैनपुर अस्पताल मे पुरी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग पूरा होगा। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश मंत्री नंदनी नेताम ने कहा की विष्णुदेव सरकार समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है इस तरह के शिविर मे लोगो को पहुंचकर योजनाओ का लाभ लेना चाहिए साथ ही उन्होने कहा सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी शासन प्रशासन की योजनाओ को ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को दिलाए।

जनपद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने गोद भराई रस्म अदा किया

इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 01 गर्भवती महिला की गोदभराई का रस्म अदा कर उपहार प्रदान किया गया। जनपद पंचायत मैनपुर के अध्यक्ष मोहना नेताम, उपाध्यक्ष नंदकुमारी राजपूत ने गोद भराई कार्यक्रम संपन्न कराई। वहीं राजस्व विभाग की ओर से स्वामित्व योजना अंतर्गत 10 हितग्राहियों को भू-अभिलेख अधिकार प्रदान किया गया 08 वर्षऍय दामिनी ध्रुरव के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा 05 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। शिविर मे अधिकारियों द्वारा आवेदनो का परीक्षण पश्चात आवश्यक कार्यवाही करते हुए अधिकांश आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया साथ ही ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभान्वित भी किया गया सभी विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों ने स्टॉल लगाकर नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस मौके पर प्रमुख रूप से मैनपुर सरपंच हनिता नायक, गोपालपुर सरपंच कंवलीबाई दीवान, खेलन दीवान, देहारगुड़ा सरपंच महेश दीवान, सरपंच भाठीगढ़ पुष्पा नेगी, डाके"वर नेगी, नीरा सांडे, उपासीन नागेश, तहसीलदार सुशील कुमार भोई, जनपद पंचायत मैनपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जे के गजभिये, बीएमओ डॉ गजेन्द्र ध्रुव, बीईओ महेश पटेल, बीआरसीसी एस के नागे, कृशि अधिकारी जागे"वर नाग, जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह धीर, जिला खाद्य अधिकारी अरविंद दुबे, जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय, सिंचाई विभाग के कार्यपालन अभियंता एस के बर्मन, लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता विप्लव धृतलहरे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विभाग के कार्यपालन अभियंता अभिशेक पाटकर, जिला चिकित्सा अधिकारी नवरत्न, लीलावती सेन, जनसंपर्क अधिकारी श्री सिदार, लिबास पटेल, चंद्रकिशोर नागेश व क्षेत्रभर के अधिकारी कर्मचारी वरिष्ठजन बड़ी संख्या मे उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शिक्षक यशवंत बघेल ने किया।

भीषण गर्मी में आई जनता को न दौड़ाएं, तीन दिन में करें समस्याओं का निपटारा : बृजमोहन

हरिभूमि न्यूज ⏭ नवापारा-राजिम

राजनेता हो तो सांसद बृजमोहन अग्रवाल जैसा। ये बाते कल बुधवार को शहर में आयोजित सुशासन तिहार शिविर के दौरान देखने और सुनने को मिला। वैसे भी श्री अग्रवाल के समर्थक कार्यकर्ता नवापारा एवं राजिम शहर में बड़ी संख्या में है। राजिम कुंभ कल्प मेले के दौरान उन्होने क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। उनके नाम से ही भीड़ जुट जाती है। लोगों को उनके ऊपर बहुत विश्वास रहता है कि एक आवेदन देंगे और काम हमारा हो जाएगा। जनता के साथ कैसे जुड़े रहना है कैसे दिल जीतना है वे बखूबी जानते है। उनका अंदाज बहुत निराला रहता है। वे जैसे ही हरिहर हायर सेकेंड्री स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोगों में अपने लोकप्रिय सांसद को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। बृजमोहन अग्रवाल की सहजता, सरलता और जनता के प्रति आत्मीय व्यवहार ने एक बार फिर लोगों का दिल यहां जीत लिया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही उन्होंने सीधे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण शुरू किए। एक-एक स्टॉल में जाकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली कि जनता द्वारा दिए गए आवेदनों पर क्या कार्रवाई हो रही है। अधिकारी जवाब देते गए और सांसद पूरे परिसर का गंभीरता से निरीक्षण करते रहे। स्टॉलों का निरीक्षण करने में ही उन्हें काफी समय लग गया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं दिखाई। जनता के प्रति उनका समर्पण और संवेदनशीलता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि इतनी भीषण गर्मी में जनता अपनी समस्याएं लेकर यहां पहुंची है, इसलिए उनके कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि सप्ताह भर तो दूर, तीन दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए।

गायत्री पीठ का नवदंपति देव दंपति प्रशिक्षण 7 को

अभनपुर। अखिल विश्व गायत्री परिवार खोरपा-भटगांव, अभनपुर द्वारा नवविवाहित एवं दाम्पत्य जीवन जी रहे दम्पत्तियों के लिए "नवदम्पति/देव दम्पति शिक्षण-प्रशिक्षण शिविर" का आयोजन 7 जून रविवार को गायत्री प्रज्ञापीठ (गायत्री मंदिर) खोरपा-भटगांव में किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि शिविर विशेष रूप से उन दम्पतियों के लिए आयोजित किया जा रहा है जो विवाह सूत्र में बंध चुके हैं तथा अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी, समुन्नत, गरिमापूर्ण, आनंदमय एवं सफल बनाना चाहते हैं। शिविर में वैवाहिक जीवन से जुड़े व्यावहारिक, वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान वर्तमान मोबाइल मीडिया एवं दूषित वातावरण के पारिवारिक जीवन पर प्रभाव, स्वाध्याय एवं आध्यात्मिक मंत्रों की उपयोगिता, संस्कारों का महत्व, बाल एवं किशोर युवाओं की विचारधारा तथा पारिवारिक सुख-शांति के लिए आध्यात्मिक वातावरण निर्माण जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाएगी। साथ ही प्रश्नोत्तरी, शंका समाधान, युग संदेश एवं आशीर्वचन का भी आयोजन रहेगा।

सुशासन तिहार में जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष व महामंत्री ने दिया आवेदन

हरिभूमि न्यूज ⏭ नवापारा-राजिम

बुधवार को शास हरिहर हाई स्कूल मैदान में आयोजित सुशासन तिहार में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष धनराज मध्यानी एवं महामंत्री सौरभ शर्मा ने नवापारा के स्थानीय व्यापारिक संघ एवं नागरिक बंधुओं की मांगों को लेकर एक आवेदन दिया गया। यह जानकारी देते हुए जिला महामंत्री सौरभ शर्मा ने बताया कि इस आवेदन में वास्तविक गंभीर मुद्दों का उल्लेख था। जिसमें नवापारा-राजिम की जीवनदायनी महानदी की सफाई अत्यंत आवश्यक है जिससे अविरल जलधारा प्रवाहित हो सके। क्षेत्रवासी अवैध रेत परिवहन से परेशान हैं, नगर में दिन के समय रेत वाहन प्रतिबंध होने के बावजूद दूसरे जिले से रेत वाहनों का आवागमन नगर में हो रहा है जिससे अनेकों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है उसे पूर्णतः प्रतिबंधित किया जावे। हरिहर हाई स्कूल मैदान के चारों ओर अतिक्रमण कर टपरी के रूप में दुकानें संचालित हो रही है, उक्त स्थान पर छोटे-बड़े सभी व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए स्थाई दुकानों का निर्माण किया जावे जिससे स्कूल एवं पालिका को आर्थिक लाभ होगा। इससे नगरवासियों को सुविधा मिलेगी व्यापार बढ़ेगा। नगर में अव्यवस्थित रूप से धार्मिक स्थल स्कूल एवं मुख्य बाजारों में मांस मटन की दुकानें संचालित की जा रही है जिसे उनके लिए एक स्थान सुनिश्चित कर संचालित किया जाए। नगर में दो मुक्तिधाम पूर्व में स्वीकृत थे जिनका कार्य आदेश जारी हो गया था लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद उक्त कार्य को निरस्त किया गया है। नगर की बढ़ती आबादी को देखते हुए पुनः पूर्व की भांति दो मुक्तिधाम की स्वीकृति प्रदान किया जावे। इसी तरह गली मोहल्ले में बिक रहे अवैध शराब पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। मांग करने वालों में जीत सिंह पूर्व उपाध्यक्ष ,राजा चावला पूर्व महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस ,राकेश सोनकर ,पूर्व उपाध्यक्ष रामकुमार शर्मा, किराना व्यापारी संघ, धनराज एंड ब्रदर्स हार्डवेयर , अनिल मेडिकल स्टोर , वस्त्र व्यापारी संघ, ज्वैलर्स एसोसिएशन आदि अनेकों व्यापारी एवं नागरिक गण शामिल हैं। नगर हित में इन सभी गंभीर मुद्दों पर सरकार तत्काल कार्यवाही करते हुए समाधान करे।

मोबाइल छोड़ खेलकूद और साइकिलिंग अपनाएं युवा

हरिभूमि न्यूज ⏭ सुरसाबांधा

विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर पूर्व जनपद उपाध्यक्ष योगेश साहू, उनकी धर्मपत्नी सुधा साहू तथा पुत्र अनादि साहू एवं अनंत साहू ने साइकिल चलाकर लोगों को स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं फिट जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर योगेश साहू ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और बदलती जीवनशैली के कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ रही हैं। ऐसे में साइकिल एक ऐसा साधन है जो स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित साइकिल चलाने से शरीर स्वस्थ रहता है, ईंधन की बचत होती है तथा प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। कहा कि युवाओं और बच्चों को मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर अधिक समय बिताने के बजाय खेलकूद और साइकिलिंग जैसी गतिविधियों को अपनाना चाहिए। इससे शारीरिक क्षमता बढ़ती है और मानसिक तनाव भी कम होता है। सुधा साहू ने कहा कि साइकिल चलाना महिलाओं और बच्चों के लिए भी लाभदायक है तथा यह स्वस्थ जीवन की ओर एक सकारात्मक कदम है। वहीं अनादि साहू और अनंत साहू ने अपने साथियों से प्रतिदिन कुछ समय साइकिल चलाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की अपील की। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साहू परिवार ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक साइकिल उपयोग करने तथा स्वस्थ, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने का आग्रह किया। इस पहल को स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने वाला प्रेरणादायक संदेश बताया गया।

आंगनबाड़ी केंद्रों में मनाया सुपोषण चौपाल

हरिभूमि न्यूज ⏭ सुरसाबांधा

क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में सुपोषण चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। सुपोषण चौपाल के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा संतुलित आहार, कुपोषण की रोकथाम, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, समय पर टीकाकरण, स्वच्छता तथा पोषण युक्त भोजन के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई। महिलाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जियों, दालों, फलों एवं अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों के नियमित सेवन के लिए प्रेरित किया गया। परियोजना अधिकारी जितेन्द्र साव के मार्गदर्शन में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बताया कि कुपोषण को दूर करने के लिए जनजागरूकता एवं सामुदायिक सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचाना विभाग की प्राथमिकता है। सुपोषण चौपाल के सफल संचालन एवं सतत मॉनिटरिंग हेतु सेक्टर सुपरवाइजर हेमलता साहू द्वारा लगातार विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पोषण अभियान के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाने तथा बच्चों एवं माताओं के स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी

हरिभूमि न्यूज ⏭ राजिम

राजिम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटके मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना राजिम थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह ग्राम सिंधौरी के ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने खेत की मेड़ पर स्थित बबूल के पेड़ से एक युवक का शव लटकते देखा। यह दृश्य देख लोगों के होश उड़ गए। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना तत्काल राजिम पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस तथा जांच के दौरान युवक की जेब से आधार कार्ड बरामद किया। इसके आधार पर मृतक की पहचान हेमराज निवासी ग्राम सरोना, थाना नरहरपुर, जिला कांकेर के रूप में हुई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को घटना की जानकारी दी।

120 किलोमीटर दूर मौत, बढ़ा रहस्य- कांकेर जिला से करीब 120 किलोमीटर दूर हेमराज का शव मिलने के कारण मामला संदिग्ध माना जा रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि कांकेर जिले का रहने वाला युवक आखिर राजिम क्षेत्र के ग्राम सिंधौरी तक कैसे पहुंचा? और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई? पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन आत्महत्या के पीछे का कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। वहीं युवक का इतनी दूर आकर फांसी लगाना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस हर संभावित एंगल से जांच कर रही है। पुलिस अब मृतक के परिजनों से पूछताछ करेगी। साथ ही उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल, लोकेशन हिस्ट्री और अन्य गतिविधियों की भी जांच की जाएगी, जिसके बाद मौत के कारणों पर से पर्दा उठ सकता है। पुलिस द्वारा पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

आरएसएस का प्रारम्भिक वर्ग आज से 100 से अधिक स्वयंसेवक लेंगे प्रशिक्षण

सुरसाबांधा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फिंगेश्वर खण्ड का तीन दिवसीय प्रारम्भिक वर्ग 5 जून से 7 जून तक नगर पंचायत कोपरा में आयोजित किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए जिला संघ चालक प्रेमलाल साहू श्यामनगर वाले ने हरिभूमि को बताया कि इस वर्ग में फिंगेश्वर खण्ड के विभिन्न ग्रामों एवं नगरों से 15 वर्ष से 40 वर्ष आयु वर्ग के 100 से अधिक स्वयंसेवक बंधु सहभागिता करेंगे। यह प्रशिक्षण वर्ग पूर्णतः आवासीय रहेगा। प्रारम्भिक वर्ग का उद्देश्य स्वयंसेवकों में संगठनात्मक दक्षता, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं राष्ट्रसेवा की भावना का विकास करना है। वर्ग के दौरान स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यपद्धति, संगठनात्मक संरचना, सामाजिक समरसता, सेवा कार्यों एवं व्यक्तित्व विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। तीन दिवसीय वर्ग में दैनिक शाखा, योग, व्यायाम, खेल, दंड प्रशिक्षण, गीत, प्रार्थना, समूह चर्चा एवं बौद्धिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों के माध्यम से स्वयंसेवकों में शारीरिक सुदृढ़ता, मानसिक विकास, आत्मविश्वास एवं टीम भावना का विकास किया जाएगा। वर्ग में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरण संरक्षण, ग्राम विकास तथा समाज के विभिन्न वर्गों के साथ समरसता स्थापित करने जैसे विषयों पर भी विशेष चर्चा होगी। वरिष्ठ संघ पदाधिकारी एवं अनुभवी कार्यकर्ता स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करेंगे तथा अपने अनुभव साझा करेंगे। आयोजन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सहभागी स्वयंसेवकों के लिए आवास, भोजन, पेयजल, स्वच्छता एवं प्रशिक्षण स्थलों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

खबर संक्षेप

रूपेश साहू ने घायल बछड़े का कराया उपचार

सुरसाबांधा। ग्राम पंचायत रोहिणा क्षेत्र में मानवता और पशु प्रेम का सराहनीय उदाहरण देखने को मिला। जानकारी के अनुसार एक छोटे बछड़े पर कुछ आवारा एवं उग्र कुत्तों ने हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्राम पंचायत रोहिणा के सरपंच रूपेश साहू मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों एवं किसान साथियों के सहयोग से बछड़े को कुत्तों के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाला। बछड़े की स्थिति को देखते हुए तत्काल पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सक को बुलाकर उसका उपचार कराया गया। समय पर उपचार मिलने से बछड़ा अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि बछड़ा किसका है और उसका मालिक कौन है। सरपंच रूपेश साहू ने कहा कि पशु-पक्षियों की रक्षा और उनकी सेवा करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। उन्होंने ग्रामीणों से भी अपील की कि किसी भी असहाय या घायल पशु को देखकर उसकी सहायता करें तथा संबंधित विभाग को सूचना दें। क्षेत्रवासियों ने सरपंच रूपेश साहू की इस संवेदनशील पहल की सराहना करते हुए इसे मानवता और जीवों के प्रति करुणा का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उनकी तत्परता और जिम्मेदारी से एक बेजुबान पशु का जीवन बच सका, जिसकी ग्रामीणों ने खुले दिल से प्रशंसा की।

1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा की शुरूआत अच्छी पहल : धनेन्द्र साहू

नवापारा-राजिम। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रदेश की जनता के लिए 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा की

शुरूआत की है। सरकार का यह दावा है कि इस हेल्पलाइन के माध्यम से स्वयं मुख्यमंत्री जी सीधे जनता की समस्याओं को सुनेंगे, एक स्वागत योग्य कदम है परंतु इस महत्वपूर्ण योजना की आधिकारिक घोषणा में कई ऐसे व्यावहारिक पहलुओं को छोड़ दिया गया है, जो पूर्व में भी जनहित की योजनाओं की विफलता का कारण बनते रहे हैं। श्री साहू ने कहा कि नागरिक सरोकार मंच इस नई व्यवस्था के सुचारू संचालन को लेकर सरकार के समक्ष कुछ अत्यंत गंभीर और जन-हितैषी प्रश्न उठाता है। कहा कि घोषणा में सबसे बड़ी कमी समय की स्पष्टता का न होना है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा यह जानकारी साझा नहीं की गई है कि मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन अथवा सप्ताह में कितने बजे से कितने बजे तक, या कुल कितने घंटे/मिनट जनता के लिए फोन पर स्वयं उपलब्ध रहेंगे। एक मुख्यमंत्री के पास प्रशासनिक और शासकीय कार्यों की भारी व्यस्तता होती है, ऐसे में 24 घंटे उनका फोन पर उपलब्ध रहना असंभव है।

कोलियारी के शीतला तालाब में स्टे के बाद भी खुदाई जारी, विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल

हरिभूमि न्यूज ▶▶| नवापारा-राजिम

ग्राम कोलियारी स्थित शीतला तालाब में जारी मिट्टी उत्खनन का मामला अब केवल राजस्व विभाग के स्थगन आदेश की अवहेलना तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि खनिज विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है। एक ओर बिना प्रशासनिक आदेश के बावजूद मशीनों और हाइवा वाहनों से उत्खनन एवं परिवहन जारी रहने के आरोप हैं, वहीं दूसरी ओर मौके पर पहुंचने के बाद भी खनिज विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी है। जानकारों के अनुसार किसी भी प्रकार के खनिज अथवा मिट्टी उत्खनन और परिवहन के लिए निर्धारित नियमों, अनुमति और रॉयल्टी संबंधी प्रावधानों का पालन अनिवार्य है। यदि उत्खनन स्थल विवादित हो, उस पर स्थगन आदेश लागू हो या वैध दस्तावेज उपलब्ध न हों, तो विभाग को तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों होती है। रायपुर खनिज विभाग के निरीक्षक प्रवीण नेताम अपने अमले के साथ गुरुवार को दोपहर जब स्थल पर पहुंचे तब वहां एक चैन माउंटेन मशीन और लगभग आधा दर्जन हाइवा वाहन खड़े थे। इसके बावजूद न तो किसी वाहन को जब्त किया गया और न ही मशीन पर कोई कार्रवाई हुई। विभागीय टीम कुछ देर निरीक्षण के बाद वापस लौट गई। यही वजह है कि अब लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि जब मौके पर गतिविधियां दिखाई दे रही थीं तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या विभाग ने दस्तावेजों की जांच की? क्या परिवहन की वैध अनुमति और रॉयल्टी पर्चियों का सत्यापन किया गया? यदि सब कुछ नियमों के अनुरूप था तो इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई ?

मौके पर मशीनें पाकर भी खाली हाथ लौटी खनिज विभाग की टीम

ग्रामीणों की सहमति क्या कानून से ऊपर?

मीडिया द्वारा पूछे जाने पर खनिज निरीक्षक नेताम ने कहा कि ग्रामीणों की सहमति से कार्य हो रहा है, इसलिए अभी काम बंद करने की समझाइश दी गई है। मौके पर एक चैन माउंटेन सहित चार हाईवा था। किसी भी प्रकार की वाहनों की जब्ती की कार्रवाई हमारे द्वारा नहीं की गई है।

निरीक्षण : विधायक ने किया तालाबों का औचक निरीक्षण, दिए पुनर्वास के निर्देश

तालाबों से हटेगा अतिक्रमण, बस स्टैंड पर बनेगा दो मंजिला हाईटेक यात्री प्रतीक्षालय

हरिभूमि न्यूज ▶▶| गरियाबंद

जिला मुख्यालय की दो प्रमुख समस्याओं तालाबों पर बढ़ते अतिक्रमण और सर्वसुविधायुक्त बस स्टैंड की कमी को लेकर प्रकाशित खबर के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। राजिम विधायक रोहित साहू ने स्वयं गरियाबंद पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। हाल ही में प्रकाशित समाचार में बताया गया था कि अतिक्रमण की चपेट में आए तालाबों के कारण वार्ड 16 सहित आसपास के क्षेत्रों में निस्तार की समस्या गहराती जा रही है। वहीं जिला मुख्यालय में यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड की लंबे समय से मांग उठ रही थी। खबर के प्रकाशन के बाद विधायक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने छीन तालाब, मरहिन डबरी और नया तालाब क्षेत्र का दौरा कर अतिक्रमण की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तालाबों के आसपास हुए अतिक्रमण को नियमानुसार हटाया जाए तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। विधायक ने कहा कि तालाब केवल जलस्रोत नहीं बल्कि पर्यावरण और स्थानीय जीवन का महत्वपूर्ण आधार हैं, इसलिए इनके संरक्षण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

खबर का असर

गुणवत्ता और समय-सीमा पर सख्त रुख

निरीक्षण के दौरान कुछ निर्माण कार्यों में तकनीकी और गुणवत्ता संबंधी कमियां सामने आने पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता के धन से होने वाले विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सभी कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी। विधायक रोहित साहू ने कहा कि नगर में तालाब संरक्षण, अतिक्रमण मुक्ति, यातायात सुधार, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले समय में गरियाबंद को एक सुव्यवस्थित, स्वच्छ और आधुनिक नगर के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रिखी राम यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर, नगर पालिका उपाध्यक्ष आशिफ मेमन सहित जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तालाबों पर अतिक्रमण और बस स्टैंड की सुविधाओं को लेकर उठे जनमुद्दों पर अब प्रशासनिक कार्रवाई शुरू होने से स्थानीय नागरिकों में समाधान की उम्मीद बढ़ गई है।

अतिक्रमण की चपेट में तालाब, 16 हजार की आबादी निस्तारी संकट से जूझ रही

जिले को मिलेगी हाईटेक यात्री प्रतीक्षालय की सौगात

नगरवासियों और यात्रियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने की दिशा में विधायक ने एक बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि गरियाबंद बस स्टैंड परिसर में आधुनिक दो मंजिला हाईटेक यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया जाएगा। प्रस्तावित भवन के भूतल में विशाल प्रतीक्षालय, आरामदायक बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं प्रथम तल पर बाहर से आने वाले यात्रियों, जरूरतमंद लोगों और अस्थायी प्रवासियों के लिए रात्रि विश्राम एवं सुरक्षित ठहरने की व्यवस्था विकसित की जाएगी।

ओड़िशा से बाइक पर ला रहे थे 9.45 लाख का गांजा, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ▶▶| मैनपुर

गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखण्ड अंतर्गत अमलीपदर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है पुलिस ने नाकाबंदी कर गांजा पकड़ने मे सफलता प्राप्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी अमलीपदर को मुखबीर सूचना मिला की दो व्यक्ति एक सिल्वर कलर के मोटर सायकल हीरो ए च ए फ डिलक्स क्रमांक सीजी–04–एलयू–2550 में भारी मात्र में अवैध गांजा रखकर परिवहन करते हुए दीगर प्रारंत उडीसा से थाना अमलीपदर क्षेत्रंतर्गत आ जा रहे है। मुखबीर के सूचना के आधार पर थाना से पुलिस टीम को घटना स्थल रवाना किया गया। घटना स्थल ग्राम बिरीघाट पहुंच कर आम रोड पर नाकाबंदी किया गया। संदिग्ध वाहन के चेकिंग के दौरान मुखबीर द्वारा बताये गये हुलिया एवं वाहन के अधार पर संदेही आरोपियों का नाम पता पुछने पर अपना नाम 01) हीरालाल केवर्त पिता लक्ष्मण केवर्त उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम मोहरा थाना चांदाहाण्डी जिला नवरंगपुर (ओडिशा) 02) टीकम टोलटिया पिता राघव उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम मोहरा थाना चांदाहाण्डी जिला नवरंगपुर (ओडिशा) कर रहने वाला बताया। आरोपियों के कब्जे से 18.900 किलो ग्राम अवैध गांजा कीमती 9.45,000 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल हीरो एचएफ

डिलक्स क्रमांक सी जी – 0 4 – एलयू – 2550 कीमती 30 लाख रूपये 02 नग मोबाइल 14 हजार कुल जुमला 09 लाख 89 हजार रूपये को समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। प्रकरण में आरोपियो के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर से अपराध धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के आरोपी 01) हीरालाल केवर्त पिता लक्ष्मण केवर्त उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम मोहरा थाना चांदाहाण्डी जिला नवरंगपुर (ओडिशा) 02) टीकम टोलटिया पिता राघव उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम मोहरा थाना चांदाहाण्डी जिला नवरंगपुर (ओडिशा) को समक्ष गवाहन के विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

सेजेस राजिम की व्याख्याता समीक्षा गायकवाड़ को पर्यावरण सम्मान

हरिभूमि न्यूज ▶▶| राजिम

क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस मिशन के अंतर्गत निजी विद्यालय कल्याण संघ समिति धमतरी द्वारा दो दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक संवर्धन कार्यशाला उत्तरदायित्व-2026 सफल आयोजन किया गया। जिसमें 120 निजी विद्यालयों के शिक्षकों को पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। संघ के पदाधिकारी मुकेश ननावरे ने बताया कि कार्यशाला में शिक्षकों को जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, विद्यालय आधारित नवाचार, स्वच्छता, सामाजिक सहभागिता तथा विद्यार्थियों में पर्यावरणीय चेतना विकसित करने संबंधी विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के विशेष सत्र में आमंत्रित सेजेस राजिम की व्याख्याता एवं सीडबॉल अभियान की प्रशिक्षक व्याख्याता समीक्षा गायकवाड़ ने उपस्थित शिक्षकों को सीडबॉल निर्माण एवं उसके वैज्ञानिक उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। गौरतलब है कि गत वर्ष व्याख्याता के मार्गदर्शन में विद्यालय के छात्रों द्वारा एक लाख से अधिक सीडबॉल तैयार किए गए थे, जिसकी सराहना केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी द्वारा भी की गई थी। इसके बाद से शिक्षिका द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और सीडबॉल निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। कार्यक्रम के समापन अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए समीक्षा गायकवाड़ को स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष तरूण भांडे, उपाध्यक्ष भूपेश चौधरी, सोमन साहू, चूड़ामणि साहू, मोहन सोनी, सचिव गजेन्द्र पटेल, सह सचिव विशेष लखोटिया, बसंत गजेन्द्र, मुकेश राव ननावरे, गोपाल साहू, राकेश साहू, पवन साहू, अवधेश सिंह मौर्य, हितेन्द्र साहू, कमलेश राठौर, दिनेशपुरी गोस्वामी, नीलू चंद्राकर, तिहारूराम सिन्हा, पारखदास मानिकपुरी, प्रदेश कोषाध्यक्ष विनोद पांडे सहित बड़ी संख्या में प्राचार्य एवं शिक्षक उपस्थित रहे।

भक्तिन माता समिति की आमसभा में वार्षिक आय-व्यय मंजूर, 31 जुलाई से पहले होंगे चुनाव

हरिभूमि न्यूज ▶▶| राजिम

राजिम भक्तिन माता समिति की वार्षिक आमसभा साहू छात्रावास परिसर राजिम में संरक्षक भुनेश्वर साहू की विशेष उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें समिति के संरक्षक विशेष आमंत्रित सदस्य समिति के सभी निर्वाचित पदाधिकारी एवं गरियाबंद,रायपुर, धमतरी, महासमुंद जिले से विभिन्न तहसील परिक्षेत्र नगर साहू संघ के पदाधिकारी गण एवं आम सदस्य उपस्थित रहे। प्रारंभ में समिति के अध्यक्ष लाला साहू ने अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक की वार्षिक आय-व्यय का विस्तृत विवरण सभा के पटल पर प्रस्तुत किया। उपस्थित सदस्यों ने आय-व्यय विवरण को ध्यानपूर्वक देखा, सुना एवं अवलोकन किया तथा दोनों हाथ उठाकर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। इस अवसर पर विशेष रूप से राजिम कुंभ मेला में आयोजित राजिम भक्तिन माता भोग भंडारा की आय-व्यय की जानकारी भी दी गई। तत्पश्चात समिति के अध्यक्ष लाला साहू ने सभा को अवगत कराया कि समिति का निर्वाचन 31 जुलाई के पूर्व कराए जाने का निर्णय लिया गया है। राजिम भक्तिन माता समिति के निर्वाचन के लिए अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के अधिकारी-कर्मचारी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक डॉ. नारायण साहू को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। साथ ही रविशंकर साहू को सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा बोधन साहू को पर्यवेक्षक मनोनीत किया गया। बैठक में मुख्य रूप से बोधन साहू ,रूपेंद्र साहू ,डॉ रामकुमार साहू ,रविशंकर साहू ,प्रदेश साहू संघ के पूर्व उपाध्यक्ष शारदा लोकनाथ साहू ,जिला साहू संघ धमतरी की उपाध्यक्ष राजेंद्र साहू, विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर विश्वनाथ साहू ,कमलेश साहू ,छोटेलाल साहू ,समिति के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वरी साहू ,आलोक साहू ,उमा साहू ,कोषाध्यक्ष भोले साहू ,महामंत्री रामकुमार साहू ,सोहन साहू ,लोकनाथ साहू ,हेमलाल साहू ,महासचिव मिंजुन साहू ,संगठन मंत्री मिश्रीलाल साहू ,डॉ ओंकार साहू, डिगेश्वर साहू, कोमल साहू, दिनेश्वर साहू, अंकेक्षक उमेंद्र साहू तहसील साहू संघ अभनपुर के अध्यक्ष तुलेश साहू राजिम तहसील अध्यक्ष जगदीश साहू फिंगेश्वर तहसील साहू संघ के अध्यक्ष खोमन साहू परिक्षेत्र अध्यक्ष पवन गुरुपंच अभनपुर गण हरी राम साहू बेलरपदाधिकारी उपस्थित थे।

कॉलेज एवं आईटीआई जाने के सरल मार्ग का भूमिपूजन

कॉलेज लिंक रोड के लिए 7 लाख की सीसी सड़क का भूमिपूजन

हरिभूमि न्यूज ▶▶| फिंगेश्वर

नगर के कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं की वर्षों पुरानी और बहुप्रतीक्षित मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है। कॉलेज रोड के लिए जाने वाले मार्ग पर बीआरसीसी भवन के पास से लेकर कॉलेज के लिंक रोड तक बनने वाली सीसी (सीमेंट कंक्रीट) सड़क का गुरुवार को भूमिपूजन संपन्न हुआ।

7 लाख की लागत से स्वीकृत इस सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ नगर पंचायत उपाध्यक्ष दीपक श्रीवास ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रीफल फोड़कर और पूजा-अर्चना कर कराया। भूमिपूजन के अवसर पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष व वर्तमान पार्षद जगदीश यादव ने बताया कि फणीकेश्वरनाथ कॉलेज और आईटीआई केंद्र तक पहुंचने के लिए यह सबसे सुगम और सरल मार्ग है। इस मुख्य मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में छात्र-छात्राओं का आना-जाना लगा रहता है। अब तक यह रास्ता ऊबड़-खाबड़ और कच्चा होने के कारण विद्यार्थियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मुख्य मार्ग पर बस से उतरकर छात्र-छात्राएं सीधे इसी लिंक रोड से होकर अपने कॉलेज और संस्थान पहुंचते हैं। इस मार्ग के पूरी तरह सीसीकरण हो जाने से छात्र-छात्राओं का सफर सुरक्षित और आसान हो जाएगा।

मीडिया की सजगता से दूर हुई समस्या, विधायक से भी आगे की मांग

नगर पंचायत उपाध्यक्ष दीपक श्रीवास ने इस महत्वपूर्ण कार्य को लेकर मीडिया के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि कॉलेज के छात्रों से जुड़ा यह बेहद संवेदनशील और प्रतीक्षित मुद्दा था, जिस पर हमारे मीडिया के साथियों ने लगातार समाचारों के माध्यम से हम सभी जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराया। इसी का सुखद परिणाम है कि आज यह सड़क बनने जा रही है। उपाध्यक्ष श्रीवास ने आगे बताया कि कॉलेज के पूरे कच्चे पहुंच मार्ग को डामरीकृत या पक्की सड़क में तब्दील करने के लिए राजिम विधायक रोहित साहू से भी विशेष मांग की गई है, जो आने वाले समय में जल्द ही पूरी होगी। इस गरिमामयी और उत्साहजनक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक और निर्माण एजेंसी से जुड़े लोग मौजूद थे। मुख्य रूप से दीपक श्रीवास (उपाध्यक्ष, नगर पंचायत फिंगेश्वर), अभिषेक सोनी (वार्ड पार्षद), जगदीश यादव (पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष व पार्षद), अनिल चंद्राकर (पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष), दीपक पोद्दार (वरिष्ठ पत्रकार), के.डी. सोनवानी (गणमान्य

नागरिक), दिलीप निषाद (संबंधित निर्माण ठेकेदार) सड़क निर्माण का कार्य विधिवत प्रारंभ होने से न केवल छात्र-छात्राओं में, बल्कि पूरे वार्ड और नगरवासियों में हर्ष की लहर है। लोगों को उम्मीद है कि ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य समय-सीमा के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा।

रासायनिक खाद को कहें ना, हरी खाद के रूप में ढैंचा अपनाकर किसान बचाएं 3 बोरी यूरिया

हरिभूमि न्यूज ▶▶| सुरसाबांधा

कृषि विभाग द्वारा किसानों को रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए हरी खाद के रूप में ढैंचा (सेसबेनिया) के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के किसानों को हरी खाद अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे खेती की लागत कम होने के साथ-साथ मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार हो सके। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ढैंचा एक दलहनी फसल है, जो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करने का कार्य करती है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और रासायनिक उर्वरकों, विशेषकर यूरिया की आवश्यकता कम हो जाती है। किसानों को बताया जा रहा है कि मानसून की शुरूआत में ढैंचा की बुवाई 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से की जानी चाहिए। बुवाई के लगभग 35 से 40 दिनों बाद, जब पौधे 1 से 1.5 मीटर ऊंचाई प्राप्त कर लें और फूल आने की प्रारंभिक अवस्था में हों, तब उन्हें ट्रैक्टर चालित डिस्क हैरो, रोटावेटर अथवा मिट्टी पलटने वाले हल की सहायता से खेत में दबाकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके बाद पर्याप्त नमी बनाए रखने पर लगभग 15 से 20 दिनों में ढैंचा पूरी तरह सड़-गलकर मिट्टी में मिल जाता है और उसके पोषक तत्व फसलों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। कृषि विभाग के अनुसार ढैंचा के उपयोग से मिट्टी में जैविक कार्बन, नाइट्रोजन एवं अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। साथ ही मिट्टी की संरचना, जलधारण क्षमता और लाभकारी सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों में भी वृद्धि होती है। इसका सकारात्मक प्रभाव आगामी फसलों की वृद्धि एवं उत्पादन पर देखने को मिलता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि ढैंचा को खेत में मिलाने से प्रति हेक्टेयर लगभग 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन उपलब्ध होती है। इतनी मात्रा में नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए सामान्यतः 90 से 130 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 2 से 3 बोरी यूरिया की बचत कर सकते हैं जिससे खेती की लागत कम होती है और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है।